

प्रेषक:

डा० रंजीत कुमार सिन्हा,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

कुलसचिव/वित्त नियंत्रक,
दून विश्वविद्यालय,
देहरादून।

शिक्षा अनुभाग-6 (उच्च शिक्षा)

देहरादून: दिनांक: 13 अगस्त, 2016

विषय:- वर्तमान वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्यय में अनुदान संख्या-11 के आयोजनागत पक्ष (Plan) के अन्तर्गत वचनबद्ध मदों में (वेतनादि) में धनराशि अवमुक्त किए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने पत्र संख्या-85/94/2016-17/FC-DU/2016, दिनांक 08.08.2016 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2016-17 में दून विश्वविद्यालय हेतु आयोजनागत पक्ष (Plan) में वेतन भत्ते आदि के लिये सहायक अनुदान में प्राविधानित धनराशि ₹0 550.00 लाख के सापेक्ष शासनादेश संख्या-345/XXIV(6)/2016-32(4)/12, दिनांक 19 अप्रैल, 2016 के द्वारा ₹0 183.33 लाख अवमुक्त की गयी है। उक्त धनराशि को घटाते हुये अवशेष धनराशि ₹0 366.67 लाख (₹0 तीन करोड़ छियासठ लाख सड़सठ हजार मात्र) की धनराशि वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-847/XXVII(1)/2016, दिनांक 26 जुलाई, 2016 में वर्णित व्यवस्थानुसार स्वीकृत करते हुए निम्नांकित प्रतिबन्धों के अधीन आपके निर्वर्तन में रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

- (1) उक्त स्वीकृत की गयी धनराशि के देयक पर उप निदेशक, उच्च शिक्षा निदेशालय, हल्द्वानी के द्वारा प्रतिहस्ताक्षरत करने के उपरान्त विश्वविद्यालय द्वारा यथा आवश्यकतानुसार मासिक व्यय की सारणी बनाकर किश्तों में किया जायेगा।
- (2) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय वास्तविक व्यय आवश्यकता के आधार ही किया जाएगा, तथा अतिरिक्त बजट की प्रत्याशा में अधिकृत धनराशि से अधिक धनराशि कदापि व्यय नहीं की जायेगी।
- (3) विश्वविद्यालय के वित्त अधिकारी द्वारा उपरोक्त स्वीकृत धनराशि का आहरण तभी किया जायेगा जबकि गत वित्तीय वर्ष/वर्तमान वित्तीय वर्ष में स्वीकृत धनराशि का नियमानुसार उपभोग कर लिया गया हो तथा कोई भी धनराशि अवशेष न हो। धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार ही किया जाएगा।
- (4) व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हो उनमें आहरण करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।
- (5) व्यय करते समय मितव्ययता के संबंध में समय-समय पर वित्त विभाग के निर्गत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। इस संबंध में वेतन मदों में मितव्ययता सुनिश्चित करने



के लिए तत्काल शीर्षक/मदवार बचत की कार्य योजना बना ली जाय। तदनुसार विशेषकर आयोजनागत पक्ष में बचत करने का वार्षिक लक्ष्य निर्धारित कर बचत किया जाना सुनिश्चित करें।

- (6) विभिन्न मदों में व्ययभार/देयता सृजित होने पर यथाशीघ्र धनराशि आहरित कर भुगतान की जाएगी एवं कोई भुगतान अनावश्यक लम्बित नहीं रखा जाएगा।
- (7) बजट मैनुअल में निर्धारित प्रक्रियानुसार कोषागार द्वारा प्रमाणित बाउचर संख्या एवं दिनांक सहित बजट की सीमा तक प्रपत्र बी0एम0-08 पर व्यय विवरण शासन के प्रशासकीय विभाग एवं वित्त विभाग को माह की अगली 05 तिथि तक अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाएगा।
- (8) यह सुनिश्चित किया जाएगा कि (वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के पैरा-162) समस्त आहरित अग्रिमों का समायोजन आहरण-वितरण अधिकारियों द्वारा 30 दिनों के अन्दर कर दिया जाय तथा डीटेल्ड कन्टीजेन्ट (डी0सी0) बिल महालेखाकार को भेज दिए जाय। विभिन्न अग्रिमों का आहरण अधिकारों के प्रतिनिधायन 2010 में दी गई सीमाओं के अनुसार ही किया जाय।

3- यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-847/XXVII(1)/2016, दिनांक 26 जुलाई, 2016 के क्रम में साफ्टवेयर के माध्यम से निर्गत विशिष्ट अलॉटमेंट आई0डी0 संख्या- (प्रति-संलग्न) द्वारा निर्गत किए जा रहे हैं।

4- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक के आयोजनागत पक्ष के अनुदान संख्या-11 लेखाशीर्षक-2202-सामान्य शिक्षा, 03-विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा, 102-विश्वविद्यालयों को सहायता, 05- दून विश्वविद्यालय-00, 43-वेतन भत्ते आदि के लिए सहायक अनुदान की सुसंगत इकाई के नामे डाला जायेगा।

संलग्नक: यथोपरि।

भवदीय,

(डा० रंजीत कुमार सिन्हा)
अपर सचिव।

संख्या-781 (1)/XXIV(6)/2016-32(4)/12, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, देहरादून।
2. कुलपति, दून विश्वविद्यालय, देहरादून।
3. जिलाधिकारी, देहरादून।
4. कोषाधिकारी, देहरादून।
5. निदेशक/उप निदेशक, उच्च शिक्षा, निदेशालय, हल्द्वानी।
6. निदेशक, एन0आई0सी0 सचिवालय, उत्तराखण्ड।
7. बजट राजकोषीय, नियोजन एवं संसाधन सचिवालय, देहरादून।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(लक्ष्मण सिंह)

संयुक्त सचिव।